Raj Express (Indore), 18th February 2025, Page- 11

स्थापना दिवस मनाया : 2024 में आईआईटी इंदौर के 35 पेटेंट को मिली वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति

आईआईटी हर साल 2.62 लाख लीटर जल करेगा संग्रहित

- पिछले वर्ष मिली 40 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाएं
- कुल 76 पेटेंट प्राप्त हुए, जिनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट शामिल

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

आईआईटी इंदौर में सोमवार को संस्थान का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सचिव डॉ. राजेश गोखले बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थापना दिवस का मुख्य आकर्षण ट्रांजिट लैब कॉम्प्लेक्स 'संवर्धन प्रौद्योगिकी विकास संकुल' का उद्घाटन था। यह एक ऐसा संकुल है जिसमें 433 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 4 प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। वहीं, इस भवन में वर्षा जल संचयन की सुविधा भी है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2.62 लाख लीटर जल संग्रहित होगा।

जेन झेड है युवा, जो देश के विकसित भारत के लक्ष्यों को करेंगे पूरा: प्रोफेसर गोखले ने कहा, मैं ऐसे युवा और प्रतिभाशाली संकाय सदस्यों व छात्रों को देखकर उत्साहित हूं और आप जेन झेड हैं, जो देश के विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आपके विचार, नवाचार, उत्साह और निर्भीकता हमारे देश को वैश्विक पटल के केंद्र में ले जाएंगे। अगर आप वाकई खुद से

पूछें कि पिछले 16 सालों में तकनीकी नवाचार के बाद से क्या बदला है, तो सबसे पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जवाब मिलेगा। भविष्य डिजिटल ट्विन और स्केलेबल इंटेलिजेंस के बारे में होगा। स्केलेबल, इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने के लिए स्वतंत्र घटकों को स्तरित करना ही जीवविज्ञान और जैव-विनिर्माण के अगले रेवल्यूशन को आगे बढ़ाएगा। साथ ही, मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम इस संगठन, इस देश, इस पारिस्थितिकी तंत्र में स्केल्ड इंटेलिजेंस के निर्माण के संदर्भ में कैसे योगदान दे सकते हैं।

आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में स्थायित्व बना रहे, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी के लिए आर्थिक लाभ सृजित हो रहे हैं, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि रोजगार उपलब्ध हों। डीएसटी में, हमारा लक्ष्य इनमें से कई गतिविधियों को एकीकृत करना है और इस तरह हम अनुसंधान, कौशल उन्नयन, निर्धारित लक्ष्यों और वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए कई बड़े स्टार्टअप में निवेश करके आज और कल की सफलता को जोड़ना चाहते हैं।

डिजाइन में स्नातक और एमसीटीई सेना अधिकारियों के लिए एमटेक: आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी ने कहा, हम डिजाइन में स्नातक कार्यक्रम, संचार एवं सूचना प्रणाली में एम.टेक. कार्यक्रम (एमसीटीई सेना अधिकारियों के लिए) और अंग्रेजी में कला स्नातकोत्तर (साहित्य और भाषा विज्ञान) की पेशकश करेंगे। पिछले वर्ष प्रमुख परियोजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है।

आठ सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार

इस अवसर पर संस्थान ने वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर रघुनाथ साहू और प्रोफेसर बिस्वरूप पाठक को सम्मानित किया गया, जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई है। वहीं, आठ सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार-इस पुरस्कार के माध्यम से अभूतपूर्व नवाचारों और तकनीकी प्रगति को सम्मानित किया जाता है जिनमें स्थाई प्रभाव बनाने की क्षमता होती है। अनुसंधान उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए 11 सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार प्रदान किए गए। संस्थान के कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और अटल सहयोग के लिए उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार भी दिए गए। हैंडबुक ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज, आईआईटी इंदौर के दूसरा संस्करण का विमोचन भी किया गया, जो आईआईटी इंदौर के संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा विकसित लगभग 180 प्रौद्योगिकियों का एक व्यापक संकलन है। यह उद्योग भागीदारों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के लिए इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर एक अमूल्य संसाधन के रूप में कार्य करता है।

प्रयोगशाला परिसर का निर्माण हो रहा

पिछले वर्ष हमें 40 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाएं मिली हैं। साथ ही, हमें कुल 76 पेटेंट प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट शामिल हैं। 2024 में, आईआईटी इंदौर के 35 पेटेंट को वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति मिली है। उद्घाटन की गई ट्रांजिट लैब के अलावा, हम 15000 वर्गफीट क्षेत्र में एक और प्रयोगशाला परिसर का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही, 100 की क्षमता वाले 4 कक्षाओं का निर्माण शुरू हो गया है। पीएम अजय बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत छात्रावास का काम भी पूरा होने वाला है। लगभग 800 की क्षमता वाले तीन नए छात्रावासों का निर्माण शुरू किया गया है। इन छात्रावासों से संस्थान को छात्रों की आवास क्षमता को 5000 से अधिक तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।